TO BE PUBLISHED IN PART-I SECTION-I OF THE GAZETTE OF INDIA

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF TEXTILES

NOTIFICATION

Udyog Bhavan, New Delhi
08th December, 2020

Sub : **Extension of operation of residuary provisions of Garments and Knitwears Export Entitlement (Quota) Policies with effect from 1st January, 2021.**

No.1/61/2004-Exports-I (1) – The Government, vide Notification No.1/61/2004- Exports-I dated 9th November, 2004, decided to enforce operation of the residuary provisions of Garments and Knitwears Export Entitlement (Quota) Policy initially for one year with effect from 1st January, 2005, and extended from time to time. These provisions have since been extended upto 31st December, 2020.

2. In order to deal with the appeal and recovery in respect of EMD forfeiture orders and existing mechanism to deal with cases of non / short performance of the quota obligation, as well as quota malpractice by the exporters and related court cases, the Government hereby decides to extend the operation of the residuary provisions of Garments and Knitwears Export Entitlement (Quota) Policy for a further one year with effect from 1st January, 2021.

3. All other terms and conditions mentioned in Para 1 of the Notification dated 9th November, 2004 shall remain unchanged.

R.K. Singh
(R.K. Singh)
Under Secretary to the Govt. of India
Ph. 23061770
Email: tepti2@nic.in

To
The Manager,
Government of India Press,
Minto Road, New Delhi-110002.

TO BE PUBLISHED IN PART-I SECTION-I OF THE GAZETTE OF INDIA

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF TEXTILES

NOTIFICATION

Udyog Bhavan, New Delhi
08th December, 2020

Sub : **Extension of operation of residuary provisions of Yarn, Fabrics & Madeups Export Entitlement (Quota) Policies with effect from 1st January, 2021.**

No.1/61/2004-Exports-I (2) – The Government, vide Notification No.1/61/2004- Exports-I dated 9th November, 2004, decided to enforce operation of the residuary provisions of Yarn, Fabrics & Made-ups Export Entitlement (Quota) Policy initially for one year with effect from 1st January, 2005, and extended from time to time. These provisions have since been extended upto 31st December, 2020.

2. The Government hereby decides to extend the operation of the residuary provisions of Yarn, Fabrics & Made-ups Export Entitlement (Quota) Policy for a further one year with effect from 1st January, 2021.

3. All other terms and conditions mentioned in Para 1 of the Notification dated 9th November, 2004 shall remain unchanged.

R.K. Singh

(R.K. Singh)
Under Secretary to the Govt. of India
Ph. 23061770
Email: teptj2@nic.in

To
The Manager,
Government of India Press,
Minto Road, New Delhi-110002.

भारत के राजपत्र के भाग-Iखण्ड-Iमें प्रकाशनार्थ

भारत सरकार
वस्त्र मंत्रालय

अधिसूचना

उद्योग भवन, नई दिल्ली
08 दिसंबर, 2020

विषय : दिनांक 1 जनवरी, 2021 से परिधान तथा निटवियर की निर्यात पात्रता (कोटा) नीतियों के शेष प्रावधानों के संचालन का विस्तार।

सं. **1/61/2004-निर्यात-I (1)** –सरकार ने दिनांक 9 नवंबर, 2004 की अधिसूचना सं. 1/61/2004-निर्यात-I के तहत परिधान तथा निटवियर की निर्यात पात्रता (कोटा) नीतियों के शेष प्रावधानों के संचालन को दिनांक 1 जनवरी, 2005 से प्रारंभ में 1 वर्ष की अवधि हेतु लागू करने और समय-समय पर विस्तारित करने का निर्णय लिया था। इन प्रावधानोंका विस्तार 31 दिसंबर, 2020 तक किया गया है।

2. सरकार एतद्वारा परिधान तथा निटवियर निर्यात पात्रता (कोटा) नीतियों के शेष प्रावधानों के संचालन को दिनांक 1 जनवरी, 2021से आगे 1 वर्ष हेतु विस्तारित करने का निर्णय लेती है।

3. दिनांक 9 नवंबर, 2004 की अधिसूचना के पैरा 1 में उल्लिखित सभी अन्य नियम व शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी।

(आर.के. सिंह)
अवर सचिव, भारत सरकार
दूरभाष 23061770
ई-मेल: teptj2@nic.in

सेवा में,

प्रबंधक,
भारत सरकार मुद्रणालय,
मिंटो रोड, नई दिल्ली-110002.

भारत के राजपत्र के भाग-I खण्ड-I में प्रकाशनार्थ

भारत सरकार
वस्त्र मंत्रालय

अधिसूचना

उद्योग भवन, नई दिल्ली
08 दिसंबर, 2020

विषय : दिनांक 1 जनवरी, 2021 से यार्न, फैब्रिक्स तथा मेड-अप्स की निर्यात पात्रता (कोटा) नीतियों के शेष प्रावधानों के संचालन का विस्तार।

सं. **1/61/2004-निर्यात-I (2)** –सरकार ने दिनांक 9 नवंबर, 2004 की अधिसूचना सं. 1/61/2004-निर्यात-I के तहत यार्न, फैब्रिक्स तथा मेड-अप्स की निर्यात पात्रता (कोटा) नीतियों के शेष प्रावधानों के संचालन को दिनांक 1 जनवरी, 2005 से प्रारंभ में 1 वर्ष की अवधि हेतु लागू करने और समय-समय पर विस्तारित करने का निर्णय लिया था। इन प्रावधानोंका विस्तार 31 दिसंबर, 2020 तक किया गया है।

2. सरकार एतद्वारा यार्न, फैब्रिक्स तथा मेड-अप्स की निर्यात पात्रता (कोटा) नीतियों के शेष प्रावधानों के संचालन को दिनांक 1 जनवरी, 2021से आगे 1 वर्ष हेतु विस्तारित करने का निर्णय लेती है।

3. दिनांक 9 नवंबर, 2004 की अधिसूचना के पैरा 1 में उल्लिखित सभी अन्य नियम व शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी।

(आर.के. सिंह)
अवर सचिव, भारत सरकार
दूरभाष 23061770
ई-मेल: tepti2@nic.in

सेवा में,

प्रबंधक,
भारत सरकार मुद्रणालय,
मिंटो रोड़, नई दिल्ली-110002.